असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते है।
– अज्ञात

धार्मिक जमावड़े की प्रवृत्ति

भारत में कोरोना अभी सामुदायिक संक्रमण का रूप नहीं ले सका है लेकिन धार्मिक जमावड़े की प्रवृत्ति को देखते हुए हम आगे को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते। दिक्कत यह है कि हमारे यहां धार्मिक आस्था को हर चीज से ऊपर माना जाता है।

राधा जोशी।

दिल्ली में एक धार्मिक आयोजन के दौरान बड़े पैमाने पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण ने देश की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी के निजामुद्दीन इलाके में लॉकडाउन शुरू होने से थोड़ा ही पहले 13–15 मार्च को तबलीगी जमात हुई थी, जिसमें भारत के अलावा मलयेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और किर्गीजिस्तान से आए 2000 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था।

इनमें से करीब 1400 लोग लॉकडाउन के बाद भी वहीं पड़े रहे, जिनमें कई को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। पिछले दिनों ये अलग–अलग राज्यों में अपने–अपने घर भी गए, जहां उनकी वजह से कितना संक्रमण फैला होगा, कहना मुश्किल है। उनमें से 6 की तेलंगाना में मौत हो गई जबकि अंडमान के कुल 10 संक्रमित लोगों में 9 वही हैं जो दिल्ली के आयोजन से लौटकर गए थे।

लॉकडाउन का मकसद ही है लोगों को समूह से अलग करना। एक जगह ढेर सारे लोगों के जमा होने से कोरोना वायरस फैलने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। इटली में हालात इतने भयावह इसलिए हुए क्योंकि फरवरी में मिलान में चौंपियंस लीग के तहत खेले गए एक फुटबॉल मैच में 40 हजार दर्शक जुटे थे। यहीं से बीमारी ने देखते–देखते पूरी इटली को गिरफ्त में ले लिया।

भारत में कोरोना अभी सामुदायिक संक्रमण का रूप नहीं ले सका है लेकिन धार्मिक जमावड़े की प्रवृत्ति को देखते हुए हम आगे को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते। लॉकडाउन के तहत धार्मिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। पंजाब में इस बीमारी के कुल चिह्नित मामलों में से आधे विदेश से आए एक ग्रंथी के संपर्कियों के हैं। पिछले दिनों चौत्र छठ पर भारी भीड़ देखी गई।

मस्जिदों में सामूहिक नमाज और मंदिरों में सामूहिक पाठ जारी है। केरल में एक पादरी को धार्मिक आयोजन के लिए गिरफ्तार किया गया। दिक्कत यह है कि हमारे यहां धार्मिक आस्था को हर चीज से ऊपर माना जाता है। उसके आगे बुद्धि–विवेक की एक नहीं सुनी जाती। लोग सोचते हैं कि धार्मिक कर्म करते हुए मृत्यु आ जाए तो इसे भी ईश्वर की इच्छा समझा जाना चाहिए।

इस बार तमाम धर्मगुरुओं ने साफ कहा था कि लोग भीड़भाड़ से बचें, घर में ही पूजा–पाठ करें, वहीं नमाज पढ़ें। लेकिन जब राजनेता ही इन निर्देशों की उपेक्षा करते हैं तो आम आदमी में गलत संदेश जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लॉकडाउन के ऐलान के बाद अयोध्या पहुंचकर पूजा–अर्चना करना एक ऐसी घटना थी जिससे बचा जा सकता था। अच्छा होगा कि हम सभी समाज की सुरक्षा को अपनी आस्था से ज्यादा तरजीह दें।

चेतना से निर्णय

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

इस दुनिया में आजाद रहना, खुद के बारे में सोचना, अपनी चेतना से निर्णय लेना, अपने विवेक से काम करना इन सब को लगभग असंभव बना दिया गया है. चर्च, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, विश्वविद्यालय, हर जगह आपसे आज्ञाकारी होने की उम्मीद की जाती है. अब तक अपनाए नियम नें लोगों को इस तरह से बर्बाद किया है कि वह पूरा जीवन हर तरह के अधिकार की गुलामी कर दासों जैसा रहता है. उसके जड़ों को काट दिया गया है ताकि उसके पास लड़ने के लिए प्रर्याप्त ऊर्जा ना हो और वह आजादी, व्यक्तित्व या किसी भी प्रकार का अधिकार पा ना सके. तब उसके पास जीवन का एक छोटा हिस्सा होगा जो कि उसे तब तक जीवित रखेगा जब तक मौत उसे इस दासता से मुक्त नहीं कर देती। बच्चे माता– पिता के गुलाम होते हैं, पत्नियां गुलाम होती हैं, पति गुलाम होते हैं, बूढ़े लोग जवान लोगों के गुलाम होते हैं क्योंकि उनके पास सारी ताकतें होती है।

संपादकीय

शहर में सन्नाटा

लॉकडाउन? ये क्या होता है? उसने कभी यह शब्द सुना भी नहीं था। उसे क्या पता था कि लॉकडाउन में सारे शहर में सन्नाटा छा जाता है। दुकानें बंद, सड़कें सुनसान और इंसान घरों में कैद हो जाते हैं। वह तो आगामी 10–15 दिनों में हजारों का फायदा होने की आस लगाए था। आमों के सीजन का उसे इंतजार था। गर्मियों में आमों पर किसका जी नहीं ललचा जाता। परसों मैं जब राशन खरीदने निकला, तो ठेले पर खुशबू बिखेरते पके आम देखकर उसकी तरफ जाने से खुद को रोक नहीं सका। उसके चेहरे पर गहरी निराशा थी। ऐसे सन्नाटे में सिर्फ दिनभर में इक्का–दुक्का ग्राहक ही आ रहे थे।

आमों की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। किसी तरह उसने अब तक उन्हें खराब होने से बचा रखा था। उसने बताया कि इस बार आमों की आवक देरी से हुई है। उसे लगा था कि लोग इनका स्वाद चखने के लिए तरस रहे हैं, सो बिक्री अच्छी होगी। पिछले साल उसने अच्छा मुनाफा कमाया था। यही सोचकर वह 40 हजार रुपये के आम 18 मार्च को मंडी से खरीदकर लाया था। 21 मार्च से वह ठाणे के नौपाडा में गोखले रोड पर अपना ठेला सजाकर बैठने वाला था। पहले दिन उत्साह से बैठा, 3 हजार रुपये की बिक्री भी की, लेकिन जब शाम को उसे पता चला कि अगले दिन 'जनता कर्फ्यू' है, सब कुछ बंद रहेगा, तो निराश हो गया। फिर उसने खुद को समझाया कि चलो, एक ही दिन की तो बात है। अगले दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे आसपास वालों से जो पता चल रहा था, वह बेचैन करनेवाला था। दो दिन उसने ठीक–ठाक बिक्री की। लेकिन 24 की शाम उसे पता चला कि 21 दिन के लिए लॉक डाउन हो रहा है।

'द सक्सेस आफ आवर स्कूल्स– स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स' (एसईक्यूआइ) में 2016–17 को संदर्भ वर्ष और 2015–16 को आधार वर्ष के रूप में माना गया है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में गिरावट

लालजी जायसवाल।

भारत में शिक्षा क्षेत्र की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में लगातार गिरावट यह प्रदर्शित करती है कि भारत में अभी भी विशेष शैक्षणिक सुधार की आवश्यकता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016–17 के दौरान स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में देश के बीस बड़े राज्यों में केरल शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद राजस्थान और कर्नाटक क्रमशरू दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे निचले पायदान पर है। 'द सक्सेस आफ आवर स्कूल्स– स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स' (एसईक्यूआइ) में 2016–17 को संदर्भ वर्ष और 2015–16 को आधार वर्ष के रूप में माना गया है। इस सूचकांक को स्कूल शिक्षा क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार छोटे राज्यों में मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा को क्रमशरू पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। इसके बाद मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। आज भी शिक्षा के स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हो पा रहा है। कुछ वर्षों

पहले जिन राज्यों का जो स्थान था, आज भी वे राज्य उन्हीं स्थानों पर बने हुए हैं।

आज उच्च शिक्षा के स्तर में भी लगातार गिरावट आ रही है। इसकी जड़ें प्राथमिक शिक्षा में निहित हैं। जब तक प्राथमिक शिक्षा में सुधार नहीं लाया जाएगा, तब तक उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार पाना संभव नहीं है। यदि प्राथमिक शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता में सुधार कर लिया जाए, तो उच्च शिक्षा की दशा और दिशा में सुधार का रास्ता आसान हो सकता है। स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। देश भर में लगभग अस्सी लाख बच्चे छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग में शामिल हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। लाखों बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं।

शिक्षा सुधार के उपायों की दिशा में हमें अन्य देशों के मॉडलों से सीख लेने की जरूरत है। शिक्षा स्तर में सुधार की एक तरकीब दक्षिण कोरिया और फिनलैंड से ली जा सकती है। इन देशों में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। वहां प्राथमिक शिक्षकों का वेतन एक प्रोफेसर के वेतन से भी अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर शिक्षा की नींव अर्थात निचला स्तर मजबूत कर दिया जाए तो उच्च स्तर पर कोई विशेष परिश्रम नहीं करना होगा। इसी कारण इन देशों की शिक्षा व्यवस्था 'नीचे से ऊपर'(डाउन टू टॉप) मॉडल पर आधारित है। लेकिन भारत में प्राथमिक शिक्षा शुरू से उपेक्षित रही है। यहां शिक्षा के प्राथमिक स्तर को दरकिनार किया जाता है।

शिक्षा के स्तर में आई गिरावट का एक बड़ा कारण शिक्षकों का अभाव है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2015–2016 से उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती में भारी गिरावट आई है। पिछले तीन वर्षों में आरक्षित स्थायी पदों में यह गिरावट सबसे ज्यादा देखने को आई है। रोजगार के शैक्षिक स्तर में अनुकूल बढ़ोतरी न हो पाने से लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान भी कम हुआ है। वर्ष 2018 के उत्तरार्ध में पचपन फीसद से अधिक कार्यरत युवाओं ने दसवीं की शिक्षा तक भी पूरी नहीं की थी।

अष्टयोग-5008

5		1		6		2
4	25	2	32		36	
			6	7		3
	31	3	42		33	
3	2	7		4	5	
	37		35	3	30	
2		6		1		4

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5007 का हल

5	3	6	4	1	7	2
4	33	2	32	2	28	7
1	5	7	6	4	2	3
6	33	5	42	3	31	6
3	2	4	6	7	5	1
7	27	3	35	5	40	5
2	5	1	3	6	7	4

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे

मोहन। हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा दोष यह भी रहा है कि हम शिक्षकों को उत्तरदायी नहीं बना पाए हैं। एक निश्चित पैटर्न पर अपना पाठ्यक्रम पूरा करवा कर वे छुट्टी पा लेते हैं। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में शिक्षकों के उत्तरदायित्वों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके तरीकों के लिए देश–विदेश के कई मॉडल उपलब्ध हैं। एक मॉडल अभिभावकों को वाउचर देने का भी है। विदेशों में कई जगह अभिभावकों को वाउचर दिया जाता है। शिक्षकों से संतुष्ट होने पर वे शिक्षक या स्कूल के खाते में वह वाउचर जमा कर सकते हैं। ऐसे किसी मॉडल को भारतीय परिस्थितियों की जरूरतों के अनुरूप संशोधित भी किया जा सकता है और कोई एकदम नया मॉडल भी सोचा जा सकता है। पर इसमें दो राय नहीं कि अपने देश में शिक्षकों को न केवल बड़ी संख्या में नियुक्त करने बल्कि उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित और प्रेरित करने की भी जरूरत है।